आंगनवाड़ी: शासकों की लूट कमाई का साधन बन कर रह गयी

फ़रीदाबाद (म.मो.) जब शासन-प्रशासन की नस-नस में भ्रष्टाचार भरा हो व लूट कमाई एकमात्र मकसद हो तो फ़िर ग़रीब बच्चों के नाम पर मिलने वाले राशन को हड़पने में भी किसी को कोई शर्म महसूस नहीं होती। इस शहर में उन गरीब बच्चों के लिये 1200 आंगनवाड़ी हैं जिनके मां-बाप मज़दूरी करने के लिये सुबह से शाम तक घर से बाहर रहने को मज़बूर होते हैं। इसलिये अधिकतर आंगनवाड़ियां मज़दूरों की स्लम बस्तियों में ही बनाई गयी हैं।

आंगनवाड़ी में बच्चों के तीन वर्ग बनाये गये हैं। पहले में एक से डेढ, दूसरे में डेढ से तीन और तीसरे में तीन से छ: वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। इनमें बच्चों की कुल संख्या 40 से 70 तक कुछ भी हो सकती है। इसलिये औसतन 1200 आंगनवाड़ियों में कुल बच्चों की संख्या 60000 से 70000 तक हो सकती है। इनका सर्वे करने पर पाया गया कि तीसरे वर्ग यानी तीन से छ: वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के ही नाम अधिक दर्ज हैं और पहले वर्ग में न के बराबर। सबसे मजेदार बात जो पहाड़ी पर स्थित नेहरू कॉलोनी में यह देखने को मिली कि वहां नाम 68 बच्चों के दर्ज हैं जो 8X8 के कमरे में बैठना तो दूर खड़े तक भी नहीं हो सकते। लगभग सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों की यही स्थिति है। इसका स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि बच्चों की दर्ज संख्या फ़र्जी है, जो कुल दर्शायी गयी संख्या का एक चौथाई भी नहीं है।

फर्जी संख्या दिखाने के पीछे असल उद्देश्य, प्रति बच्चे के हिसाब से मिलने वाले राशन को हड़पना है अर्थात तीन चौथाई से अधिक फ़र्जी बच्चों के नाम पर मिलने वाला राशन हड़प लिया जाता हैं। इस लूट में से केन्द्रों पर कार्यरत कामगारों को तो मात्र खाना भर ही नसीब होता है, असल माल तो ऊपर तक बैठे अधिकारी लोग बाहर की बाहर यानी खरीदारी करते वक्त ही डकार जाते हैं।

प्रत्येक केन्द्र पर एक वर्कर जिसका वेतन 12000 मासिक है तथा एक हेल्पर 4000 मासिक पर रखे हैं। इनका काम बच्चों की देखभाल व उनके साथ बातचीत करना व हो सके तो कुछ पढ़ाना-लिखाना होता है। खाना पकाने के लिये स्वयं सहायता ग्रुप के नाम से एक टोली है। जिसे एक रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से पैसे मिलते है। इस ग्रुप में दो से अधिक महिलायें कभी नहीं होती। एक बस्ती में बने दो से तीन केन्द्रों को ये ग्रुप बड़ी आसानी से सम्भाल लेते हैं। सुधी पाठक समझ गये होंगे कि बच्चों की चौगुणी संख्या दर्शाने से इनकी दिहाड़ी भी ठीक-ठाक बन जाती है। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि रखे गये उक्त स्टाफ में से अधिकांश की शैक्षणिक एवं आवासीय वैरिफिकेशन आज तक नहीं हुई। इन केन्द्रों का तयशुदा समय प्रात: नौ बजे से सांय तीन बजे तक है, लेकिन कोई भी केन्द्र 10 बजे से पहले चालू नहीं होता। इसी तरह शाम को भी समय से पहले ही बंद कर दिये जाते हैं। इन केन्द्रों की निगरानी करने के लिये 17 सुपरवाइज़र तो तैनात हैं पर नौ पद अभी रिक्त पड़े हैं। सुपरवाइज़रों के ऊपर 6 पद सीडीपीओ के हैं जिनमें से चार अभी रिक्त हैं। इसके ऊपर एक प्रोग्राम अफ़सर यानी ज़िला महिला एवं बाल विकास अधिकारी होती है। इन सबके ऊपर ज़िला उपायुक्त अपने अतिरिक्त उपायुक्त एवं एसडीएम के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। सब मिल कर कैसा नियंत्रण एवं प्रशासकीय देख रेख कर रहे हैं उसका यह एक छोटा सा उदाहरण मात्र है।

नियमानुसार यह केन्द्र किसी कार्यकर्ता अथवा कर्मचारी के अपने या रिश्तेदार के घर पर नहीं चलाया जा सकता, परन्तु अधिकांश केन्द्र इसकी उल्लंघना करके ही चलाये जा रहे हैं। दर-असल इस तरह के प्रोजेक्ट में जब न तो किसी को न्यूनतम वेतन मिले और न ही किसी किस्म की सरकारी सुविधा, जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है तो नियमों का उल्लंघन करके ही कार्यकर्ता एवं कर्मचारी अपनी गुजर-बसर कर सकते हैं। ऊपर बैठे अधिकारीगण इनकी अनियमितताओं को नजरंदाज करते हैं तो चुपचाप माल भी डकार जाते हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार बच्चों की गिनती के हिसाब से दाल, चावल, गेहूं, सरसो का तेल, रिफाइंड तेल, चीनी, मूंगफ़ली, सोयाबीन आदि अनेकों चीजें बच्चों के नाम पर खरीदी जाती हैं। समझा जा सकता है कि तमाम खरीद तो होती है, पर रजिस्टरों में दर्ज बच्चों की संख्या के आधार पर वितरित होती है मात्र एक चौथाई से भी कम बच्चों में। स्पष्ट है कि बाकी माल वे सब अधिकारी डकार रहे हैं जिनकी ड्यूटी इस चोरी को रोकने की है। यानी अधिकारीगण ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि बिल्ली दूध की रखवाली करती है।

ऐलनाबाद चुनाव: देवी लाल से लेकर दुष्यंत तक सभी भाजपा प्रेमी हैं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि ऐलनाबाद विधासभा क्षेत्र में न पहले कुछ उनके पल्ले था और न आज है। आज तो कुछ भी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जो थोड़ा-बहुत दो साल पहले था उसका भी सफाया हो चुका है। कूटनीतिक समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा उपचुनाव से बच निकलने की अपेक्षा भाजपा ने हरियाणा के बदनामतरीन एवं पिटे हुए मुहरे गोपालकांडा के भाई गोविंद को अपना प्रत्याशी बनाकर खड़ा कर दिया। इसकी अपेक्षा भाजपा कह सकती थी कि यह सीट न पहले हमारी थी और न आज हमारी है। अभय चौटाला ने इस सीट से त्यागपत्र देकर सीट खाली की है, वही दोबारा इस पर चुनाव लड़ लें।

अभय चौटाला पर सवाल उठता है कि उन्होंने क्यों तो त्यागपत्र दिया था और अब क्यों दोबारा इसी सीट से विधायक बनने को लालायित हैं? जो किसान आन्दोलन उस वक्त चल रहा था, आज तो वह और भी गंभीर स्थिति में जा पहुंचा है। लगता है कि अभय नाखून कटाकर शहीद होने का प्रयास कर रहे थे। वे समझते होंगे कि उनकी इस 'कुर्बानी' पर राज्यभर के किसान उन पर फ़िदा हो जायेंगे जिससे सत्ता प्राप्ति का रास्ता उनके लिये खुल जायेगा। लेकिन ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा।

विधायक पद से त्यागपत्र को लेकर कांग्रेस का मानना तो यह है कि अभय सिंह, उसके द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर खट्टर के विरुद्ध मतदान नहीं करना चाहते थे। अर्थात अभय के मन में कहीं न कहीं भाजपा सरकार के प्रति मोह छिपा हुआ है जिसे उन्होंने त्यागपत्र देकर बेपर्दा कर दिया। भाजपा के प्रति चौटाला खानदान का मोह एवं गठजोड़ किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्वर्गीय देवी लाल ने 1977 में तो ओम प्रकाश चोटाला ने 1998 में भाजपा से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। इतना ही नहीं पंजाब में भाजपा की सहयोगी एवं धर्म की राजनीति करने वाली अकाली पार्टी से भी इस परिवार की पूरी घनिष्ठता रही है।

ऐसे में यदि दुष्यंत ने सत्ता की भूख मिटाने के लिये भाजपा से गठबंधन कर लिया तो क्या गुनाह कर दिया? राजनीतिक समझ रखनेवालों का मानना है कि यदि दुष्यंत की जगह अभय सिंह के पास 10 विधायक होते तो वे भी सत्ता की मलाई चाटने भाजपा के चरणों में जा पड़ते। लगता है कि आज का किसान आन्दोलन इस राजनीतिक सच्चाई को समझने लगा है। इसी समझदारी के चलते जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे सैंकड़ों किसानों ने ओम प्रकाश चौटाला को बोलने के लिये अपना माइक देने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक इन्तजार करने के बाद ओम प्रकाश अपनी गाड़ी पर लगे माइक से ही किसानों को राम-राम कह कर चलते बने।

इन मौजूदा हालात को देखते हुए अभय एवं ओम प्रकाश चौटाला के लिये ऐलनाबाद की राह आसान नहीं है। बेशक गोविंद कांडा की तरह इन्हें धक्के तो न मारे जाएं लेकिन वोट भी ज्यादा मिलने की सम्भावनायें नज़र नहीं आती। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जरूर मुंह धोकर सत्ता के निकट पहुंचने के ख्वाब देख सकती है, परन्तु किसान नेता गुरनाम सिंह चिढ़ूनी उनका यह हसीन ख्वाब तोड़ने के लिये वहां पर डटे खड़े हैं। इसके पीछे किसान आन्दोलन की समझ है कि कांग्रेस ने ही कौन से भले काम किसानों या अन्य मेनतकश वर्ग के लिये कर छोड़े थे? भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही लुटेरी पूंजी के लिये नीतियां बनाने व क्रियान्वित करने वाली हैं।

प्रदूषण, नियंत्रण से मुक्त! केवल लूट से युक्त!!

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिन प्रतिदिन शहरवासियों को प्रदूषित हवा के आंकड़े बताकर डराया जाता है और फिर इसके नाम पर तरह-तरह से लूटा जाता है। लूट के लिये तो पूरा एक विभाग ही बना दिया गया है जिसका नाम केवल कंसेंट यानी रजामंदी देना है जिसके लिये वह सरकारी फीस के अलावा अपनी जेब के लिये भी वसूली करता है।

सर्वविदित है कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक धूल कण होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं जिससे भयंकर श्वास रोग हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सड़कों से उड़ने वाली धूल होती है। बीते करीब छह माह से शहर में इस तरह की धूल ने नये कीर्तिमान स्थापित कर दिये हैं। शहर के मध्य स्थित हार्डवेयर चौक से उड़ने वाली धूल चारों ओर पचास-पचास मीटर तक फैली रहती है। इसी चौक से प्याली चौक व सैक्टर 22-23 तक जाने वाली मुख्य सड़क के अलावा भीतरी सड़कों पर सदैव धूल का गुबार बना रहता है।

हाईवे केबाटा मोड़ से लघु सचिवालय की ओर जाने वाली सड़क तो लगभग सदैव टूटी रहने के कारण धूल धूसरित रहती है। इससे भी भयंकर स्थिति है हाईवे के बाईपास को जोड़ने वाली सड़क की जिसके एक ओर सैक्टर-15 व दूसरी और 16 है। यह बीते करीब आठ माह से नदारद है, मरम्मत के नाम पर लाल मिट्टी से सड़कों को भरा जाता है, जाहिर हे इतने अधिक ट्रैफिक के चलते इस मिट्टी ने तो उड़ना ही उड़ना है। बिल्कुल यही हालात मेट्रो अस्पताल के समने व पीछे वाली सड़क के है। ये तो कुछ उन विशेष सड़कों का उल्लेख है जो शहर के मुख्य एवं पॉश इलाकों में हैं, बाकी अन्य सड़के तो विभिन्न कॉलोनियों में है उनका विवरण तो बहुत चौड़ा है।

वायु प्रदूषण के नाम पर जल्द ही भवन निर्माणों पर पाबंदी लगा दी जायेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो भवन निर्माताओं से, इस माह में करीब 58 लाख का जुर्माना भी वसूल कर लिया है। यहां के नगर निगम अधिकारी धूल ढकने के नाम पर ट्रैक्टर टेंकरो से पानी छिड़कने के नाम पर ठीक-ठाक 'कमाई' कर लेंगे। सड़कों पर झाड़ू लगाने व उड़ने वाली धूल से बचने के नाम पर निगम ने करोड़ों रुपए के दो ऐसे वाहन खरीद डाले हैं जो सड़क पर मशीनी झाड़ू लगाते हुए धूल को अपने भीतर खींच लेते हैं। अब इन अक्ल के दुश्मनों को कौन समझाये कि इस तरह की मशीनें केवल वहां उपयोगी होती हैं जहां सडकें होती हैं न कि मिट्टी से भरे गड्ढों के लिये। आगामी दो-चाह माह में ये मशीनें बिगड़ जायेंगी तो इनकी मरम्मत के नाम पर मोटे बिल बनेंगे और अन्त में ये कबाड़े के भाव बेच दी जायेंगी।

खबर मरम्मत

- जुम्मन मियां पंक्चर वाले

बीजेपी को चंदा दो बदले में एयरलाइन लो

सरकार ने आखिरकार एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया। इस बिक्री के विवरण के अनुसार टाटा कंपनी एयर इंडिया का 15300 करोड़ रुपया कर्ज अपने सर लेगी और 2700 करोड़ रुपया नकद सरकार को देगी। बदले में सरकार उसको 121 जंबो जेट हवाई जहाज वाली कंपनी देगी। इनमे से 70 जेट जहाज, जो 2018 में ही आए है, की कीमत एक लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। बाकी जहाज लगभग 30000 करोड़ के है। टाटा ने वित्त वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा, लगभग 400 करोड़ रुपया, चुनावी चंदा बीजेपी को दिया है।

यानी बीजेपी ने 400 करोड़ रुपए चंदे के बदले टाटा को एक लाख तीस हजार करोड़ की एयरलाइन दिलवा दी और बाकी 46262 करोड़ रुपए का लोन छोड़ दिया सरकार के ऊपर जिसे हम सबने भरना है, टैक्स देकर। आपने भी कोई हाउस लोन वगैरा ले रखा है तो बीजेपी को चंदा दो और लोन माफ करवा लो। योजना सिर्फ ईमानदार प्रधानमंत्री मोदीजी के रहने तक खुली है।

सूचना के अधिकार की हालत पतली

सतर्क नागरिक संगठन नामक संस्था द्वारा ओडिशा राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग में अपील का निपटारा होने में लगभग 7 साल का समय लगता है। एसएनएस के अनुसार राष्ट्रीय सूचना आयोग भी अपील का निपटारा करने में लगभग दो साल का समय लेता है हालांकि एक साल से चार रिक्त स्थान भरने के बाद से आयोग ने 33742 मामले निपटा कर अपना काफी बोझ कम किया है। संगठन ने पाया है की इतने मामले इकठ्ठे होने का कारण राज्य और राष्ट्रीय सूचना आयोग में स्टाफ की कमी व उसकी अकर्मण्यता दोनो है।

सूचना आयोग न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे लेकिन उनमें सदस्यो की नियुक्ति न करके उनको पंगु बनाने में सरकार सफल रही है। लगता है मौजूदा सरकार की लोगो को न्याय दिलाने में कुछ ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद सरकार को हाल ही में कुछ नियुक्ति करने पर मजबूर होना पड़ा है। शायद सरकार चाहती है की लोग सड़कों पर ही लड़ लड़ाकर त्वरित न्याय प्राप्त कर ले, सूचना आयोगों के चक्कर में अपना समय न खराब करे।

भुखमरी बढ़ी, खैरात बंटी

साल 2021के लिए जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक मैं भारत और सात अंक फिसलकर 94 से 101वे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार ने इसके लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया है।

उधर लोगो ने लंगर लगाए है और माता के जागरण में कंजक जिमाने मै भी कमी नहीं छोड़ी है, यानी खैरात बांटने का काम बढ़ा है ।सरकारी भी और प्राइवेट भी।

कमाल है की उसी कोरोना महामारी के कारण अदानी और अदानी की संपत्ति में तो दस गुणा बढ़ोतरी हो गई और सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने के बावजूद गरीब और गरीब हो गए और देश को भुखमरी सूचकांक में 7 अंक नीचे घसीट ले गए। ये गरीब भी पता नहीं कितना बड़ा पेट लिए है, सरकार का करोड़ों का मुफ्त राशन खाकर भी भुखमरी बढ़ाए जा रहे है। या कही ऐसा तो नहीं की गरीबों का हिस्सा अंबानी अदानी डकार रहे हो जिससे उनके पेट फूलते जा रहे हों।

अंतिम मिसरा

अगर तुम कोयले से दीवारों पर आई लव यू फलानी नही लिखते फिरते तो आज बिचारे मोदी कोयले की किल्लत से नहीं जूझ रहे होते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06